BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 485/2024
(I.A. No. 560/2025)

Dr. Ajay Kumar & Ors. Applicant(s)

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

I.A. No. 560/2025
(By Bhanu Sahay)

INDEX

Sr. no	Particulars	Page no.
01	Additional Submission With Affidavit	1-25
02	to the Photograf dated 14.01.2026	26-36

दिनांक .01.2026

प्रार्थी/आवेदक

भानू सहाय

(भानू सहाय)

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 485/2024
(I.A. No. 560/2025)

Dr. Ajay Kumar & Ors. Applicant(s)

Versus

Union of India & Ors. Respondent(s)

I.A. No. 560/2025
(By Bhanu Sahay)

ADDITIONAL SUBMISSION ON BEHALF OF APPLICANT/INTERVENOR

श्रीमान् जी,

विनम्र निवेदन है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 तथा उत्तर प्रदेश पार्क, खेल के मैदान और खुले स्थान (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975 के प्रावधानों और माननीय सुप्रीम कोर्ट एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) द्वारा पारित आदेशों, दिशानिर्देशों एवं गाइडलाइन के प्रत्यक्ष उल्लंघन के अंतर्गत, झांसी महायोजना–2021 में महारानी लक्ष्मी बाई मेडिकल कॉलेज, झांसी तथा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय, झांसी से सन्निहित भूमि/पहाड़ी पर प्रस्तावित प्रखंडीय पार्क की भूमि/पहाड़ी में झांसी प्रशासन और झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की कथित मिलीभगत से सैकड़ों वृक्षों और पहाड़ी की अवैध कटाई कर नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, व्यावसायिक एवं आवासीय अनधिकृत/अवैध निर्माण किए जा रहे हैं, जिससे पर्यावरण को गंभीर एवं अपरिवर्तनीय क्षति पहुंच रही है।

उक्त प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक और वास्तविक परिदृश्य को माननीय न्यायाधिकरण के संज्ञान में लाने के उद्देश्य से, आवेदक की ओर से यह आवेदन अंग्रेजी अनुवाद के साथ अत्यंत आदरपूर्वक प्रस्तुत किया जा रहा है। साथ ही, आवेदन के साथ संबंधित अति-प्रासंगिक अभिलेख, साक्ष्य और अन्य दस्तावेज संलग्न किए जा रहे हैं, ताकि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा पूरे प्रकरण का सम्यक अवलोकन और उचित निर्णय लिया जा सकेः-

Respected Sir,

It is most respectfully submitted that in blatant violation of the provisions of the *Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973* and the *Uttar Pradesh Parks, Playgrounds and Open Spaces (Preservation and Regulation) Act, 1975*, as well as in direct contravention of the orders, directions and guidelines passed by the Hon'ble Supreme Court and the Hon'ble National Green Tribunal (NGT), on the land/hill earmarked as a proposed Sectoral Park in the Jhansi Master Plan–2021, situated adjacent to Maharani Laxmi Bai Medical College, Jhansi and Bundelkhand University, Jhansi, large-scale illegal felling of hundreds of trees and cutting of the hill is being carried out. It is further submitted that with the alleged

connivance of the officers of the Jhansi Administration and the Jhansi Development Authority, unauthorized/illegal constructions such as nursing homes, pathology centers, medical stores, commercial and residential buildings are being raised on the said land/hill, thereby causing serious and irreversible damage to the environment.

That with a view to bringing the factual and actual scenario relating to the aforesaid matter to the kind notice of the Hon'ble Tribunal, the present application is being most respectfully submitted on behalf of the Applicant along with its English translation. Relevant and highly material records, evidence and other documents pertaining to the case are also being annexed with this application, so as to enable the Hon'ble Tribunal to have a comprehensive appreciation of the entire matter and to pass appropriate orders in accordance with law.

1. यह कि उपरोक्त प्रखंडीय पार्क और पहाड़ की भूमि पर वर्तमान में लगातार पहाड़ की भूमि व पेड़ काटकर अवैध निर्माण किया जा रहा है जो झांसी महायोजना 2001, 2021 और वर्तमान महायोजना 2031 में आरक्षित है । जिसे मूल आवेदन के पृष्ट सं. 27 व 28 एवं अभिलेख सं. 456, 457, 460, 461, 468 लगायत 478 पर दिखाया गया है।

1. That on the aforesaid block park and hill land, at present, illegal construction is being continuously carried out by cutting the hill land and trees, which is reserved in the Jhansi Master Plans 2001, 2021, and the present Master Plan 2031. The same has been shown on pages 27 and 28 of the original application and on record pages Nos. 456, 457, 460, 461, and 468 to 478.

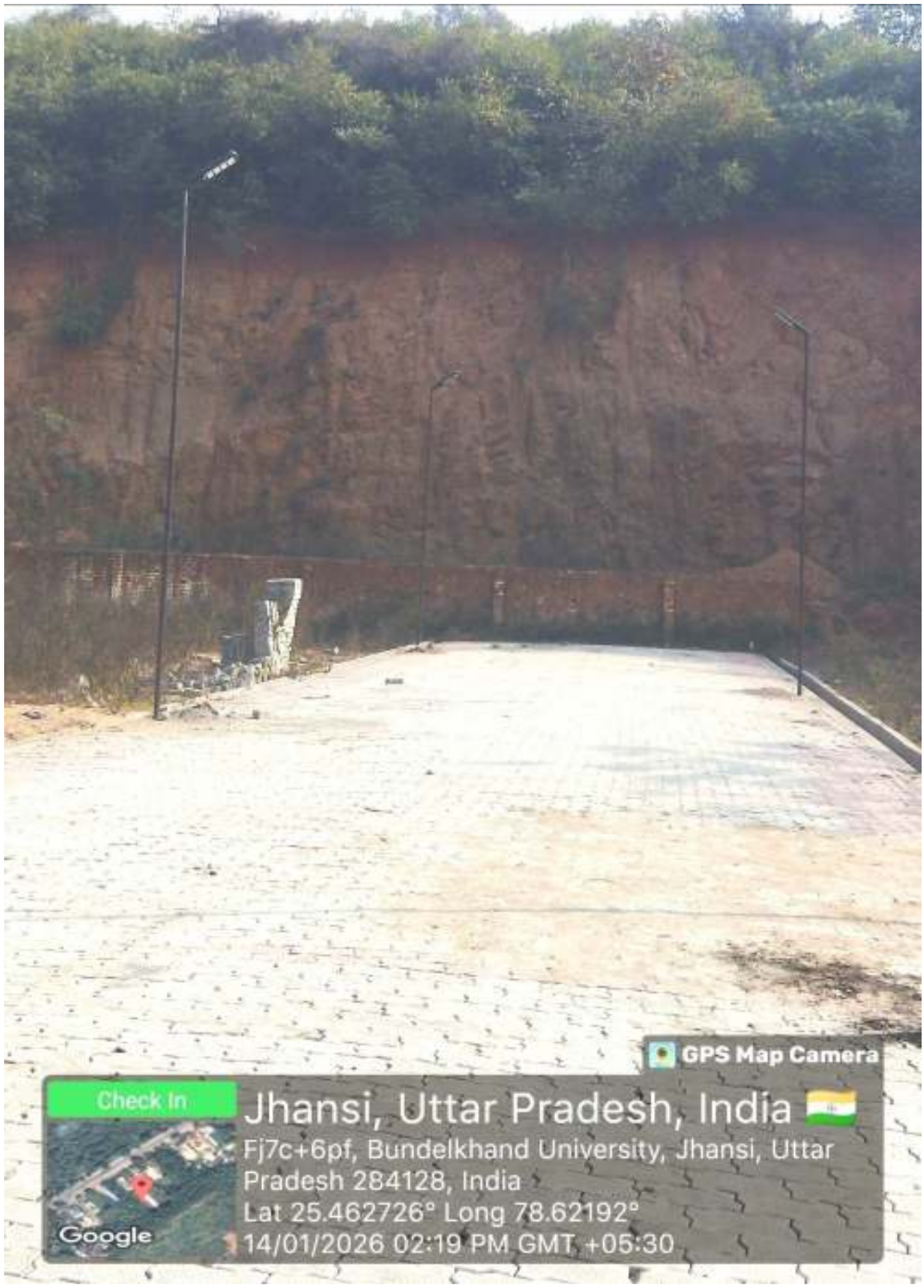

2. यह कि प्रतिवादी संख्या–10 नगर निगम झांसी द्वारा उपरोक्त प्रखंडीय पार्क और पहाड़ के कुछ आराजी भूमि की खतौनी दाखिल की गई है जिसमें शासकीय भूमि जो टौरिया, पहाड़, पहाड़ी शामिल है जिसे अभिलेख सं. 106 लगायत 134 पर देखा जा सकता है।

2. That the Respondent No. 10, Municipal Corporation, Jhansi has filed the Khatauni of the aforesaid zonal park and some land of the hill, wherein the government land recorded as Tauriya, hill and hilly area has been shown, which can be seen in record numbers 106 to 134.

3. यह कि प्रतिवादी संख्या 7 तथा 10 की मौन स्वीकृति, संरक्षण में भू-माफियाओं द्वारा उक्त प्रखण्डीय पार्क एवं पहाड़ी/हरित भूमि पर स्थित वृक्षों की कटान कर तथा पहाड़ी की प्राकृतिक संरचना को क्षतिग्रस्त करते हुए अतिक्रमण एवं अनधिकृत/अवैध निर्माण निरंतर किया जा रहा है। उक्त अवैध गतिविधियाँ प्रतिवादी अधिकारियों की सहभागिता, संरक्षण के बिना संभव नहीं हैं। उक्त तथ्य संलग्न फोटोग्राफ दिनांक 14.01.2026 और मूल आवेदन के पृष्ठ संख्या 25 एवं 26, तथा IA No. 560/2025 के पृष्ठ संख्या 6 से 14 से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होते हैं, जिनसे यह निर्विवाद रूप से सिद्ध होता है कि भ्रष्ट आचरण एवं निजी स्वार्थों से प्रेरित होकर प्रतिवादियों द्वारा अपने विधिक एवं वैधानिक दायित्वों का जानबूझकर उल्लंघन किया गया है तथा अवैध निर्माणों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है।

3. That with the silent consent and protection of Respondent Nos. 7 and 10, land mafias are continuously carrying out encroachment and unauthorized/illegal constructions on the said zonal park and hill/green land by cutting trees situated thereon and by damaging the natural structure of the hill. These illegal activities are not possible without the participation and protection of the respondent officers. The said facts are clearly proved from the photographs dated 14.01.2026, pages 25 and 26 of the Original Application, and pages 6 to 14 of IA No. 560/2025, which incontrovertibly establish that due to corrupt practices and motives driven by personal interests, the respondents have knowingly violated their legal and statutory duties and have provided protection to illegal constructions.

P.T.O. 05

4. यह कि मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रधान पीठ, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या–380/2018 *पार्क एवेन्यू प्लाट होल्डर्स वेलफेयर सोसाइटी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य* में पारित आदेश दिनांक 18.01.2019 के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 25.01.2019 को बैठक आयोजित की गई, जिसके उपरान्त शासनादेश संख्या–194/8-3-19-206 विविध/2018 दिनांक 05.02.2019 निर्गत किया गया, जिसमें महायोजनाओं में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल एवं हरित पट्टिका के संरक्षण तथा अवैध निर्माणों की रोकथाम हेतु बाध्यकारी निर्देश जारी किए गए। जो मूल आवेदन के पृष्ठ संख्या 10, 11, एवं 12 पर है।

4. That in compliance of the order dated 18.01.2019 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No. 380/2018, *Park Avenue Plot Holders Welfare Society vs. Union of India & Others*, a meeting was convened on 25.01.2019 under the chairmanship of the Principal Secretary, Housing and Urban Planning Department, Government of Uttar Pradesh, pursuant to which Government Order No. 194/8-3-19-206 Misc./2018 dated 05.02.2019 was issued, laying down mandatory directions for protection of parks, open spaces and green belts proposed in the Master Plans and for prevention of illegal constructions therein. **as placed at pages 10, 11 and 12 of the Original Application**.

1. यह कि उक्त शासनादेश द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि महायोजनाओं में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल एवं हरित पट्टिका को केवल नियोजनात्मक प्रस्ताव न मानकर वैधानिक संरक्षण प्रदान किया जाना आवश्यक है, जिससे इन क्षेत्रों में निजी व्यक्तियों द्वारा स्वामित्व के आधार पर अनधिकृत क्रय-विक्रय एवं निर्माण कार्य न किया जा सके, जैसा कि मा० अधिकरण द्वारा अपने आदेश में व्यक्त चिंता के अनुरूप है।

1. That by the aforesaid Government Order it has been clearly stipulated that the parks, open spaces and green belts proposed in the Master Plans are not to be treated merely as planning proposals, but are required to be accorded statutory protection, so as to prevent unauthorized sale and construction by private individuals on the basis of ownership, in consonance with the concern expressed by the Hon'ble Tribunal in its order.

2. यह कि शासनादेश के अनुसार समस्त विकास प्राधिकरणों, विनियमित क्षेत्रों एवं आवास एवं विकास परिषद को यह निर्देशित किया गया कि वे अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी महायोजना में अंकित पार्क, खुले स्थल एवं हरित पट्टिका से सम्बन्धित भूमि का गाटा संख्या, खसरा संख्या, आराजी संख्या एवं क्षेत्रफल सहित विस्तृत विवरण तैयार कर राजस्व विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि उक्त भूमि को खतौनी एवं अन्य राजस्व अभिलेखों में पृथक श्रेणी के रूप में अंकित किया जा सके।

2. That in terms of the Government Order, all Development Authorities, Regulated Areas and the Housing and Development Council were directed to prepare detailed particulars of land earmarked as parks, open spaces and green belts in the effective Master Plans within their respective jurisdictions, including Gata number, Khasra number, Arazi number and area, and to furnish the same to the Revenue Department, so that such land may be recorded as a separate category in the Khatauni and other revenue records.

3. यह कि शासनादेश में यह भी अनिवार्य किया गया है कि महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल एवं हरित पट्टिका के विरुद्ध जहाँ-जहाँ अवैध निर्माण विद्यमान हैं, वहाँ तत्काल सर्वेक्षण कर ऐसे निर्माणों को रोका जाए तथा उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 एवं अन्य पर्यावरणीय विधानों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए, जिससे पर्यावरणीय क्षति की पुनरावृत्ति रोकी जा सके।

3. That the Government Order further mandates that wherever illegal constructions exist contrary to the parks, open spaces and green belts proposed in the Master Plans, immediate surveys shall be conducted, such constructions shall be restrained, and strict action shall be taken under the provisions of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 and other applicable environmental laws, so as to prevent recurrence of environmental damage.

4. यह कि शासनादेश के अनुपालन में यह भी निर्देशित किया गया है कि महायोजना में ग्रीन बेल्ट, हरित पट्टिका अथवा पार्क क्षेत्र में आने वाली भूमि के विक्रय विलेख के समय दोनों पक्षों से शपथ पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा कि विक्रय की जा रही भूमि प्रतिबंधित भू-उपयोग की श्रेणी में नहीं आती है, तथा यदि भूमि प्रतिबंधित श्रेणी में आती है तो विक्रय विलेख में यह स्पष्ट टिप्पणी अंकित की जाएगी कि महायोजना के विरुद्ध किसी भी प्रकार का निर्माण होने पर विक्रय विलेख स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं भूमि बिना किसी मुआवजे के राज्य सरकार में निहित हो जाएगी।

4. That in compliance of the Government Order it has also been directed that at the time of execution of sale deeds of land falling within green belts, green strips or park areas as per the Master Plan, affidavits shall mandatorily be obtained from both parties stating that the land proposed to be sold does not fall under restricted land use, and in case the land falls under such restricted category, an explicit endorsement shall be incorporated in the sale deed to the effect that any construction in violation of the Master Plan shall result in automatic cancellation of the sale deed and the land shall vest in the State Government without payment of any compensation.

5. यह कि शासनादेश द्वारा यह भी निर्देशित किया गया है कि पार्क एवं हरित पट्टिका से सम्बन्धित तैयार की गई सूचियों को समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए, सम्बन्धित स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाए जाएं तथा समस्त विकास प्राधिकरणों की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए, जिससे आम नागरिकों को महायोजना के अनुसार वास्तविक भू-उपयोग की जानकारी प्राप्त हो सके और भविष्य में अवैध लेन-देन रोका जा सके।

5. That the Government Order further directs that the lists prepared in respect of park and green belt lands shall be published in newspapers, information boards shall be installed at the concerned sites, and the same shall also be uploaded on the websites of all Development Authorities, so as to ensure public awareness regarding the actual land use as per the Master Plan and to prevent illegal transactions in future.

6. यह कि शासनादेश में महायोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु "महायोजना कार्यान्वयन निधि" के सृजन तथा Transferable Development Rights (TDR) से सम्बन्धित बायलॉज शीघ्र लागू किए जाने का निर्देश दिया गया है, ताकि पार्क, खुले स्थल एवं हरित पट्टिका हेतु आरक्षित भूमि का अर्जन एवं विकास वैकल्पिक विधियों से भी सुनिश्चित किया जा सके।

6. That the Government Order provides for creation of a "Master Plan Implementation Fund" for effective implementation of the Master Plans and also directs that bye-laws relating to Transferable Development Rights (TDR) be framed and enforced at the earliest, so that acquisition and development of land reserved for parks, open spaces and green belts may also be ensured through alternative mechanisms.

7. यह कि याचिकाकर्ता का यह विनम्र कथन है कि उपर्युक्त शासनादेश के स्पष्ट एवं बाध्यकारी निर्देशों के बावजूद अनेक जनपदों/विकास प्राधिकरणों में आज भी महायोजना में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल एवं हरित पट्टिका भूमि पर न तो राजस्व अभिलेखों में अपेक्षित अंकन किया गया है और न ही अवैध निर्माणों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की गई है, जो कि मा० अधिकरण के आदेशों तथा शासनादेश दोनों की अवहेलना है।

7. That it is the humble submission of the Applicant that despite the clear and mandatory directions contained in the aforesaid Government Order, in several districts and Development Authorities neither the requisite entries have been made in the revenue records in respect of land earmarked for parks, open spaces and green belts in the Master Plans, nor has any effective action been taken against illegal constructions thereon, which amounts to non-compliance of the orders of the Hon'ble Tribunal as well as the Government Order.

5. यह कि महायोजनाओं में प्रस्तावित पार्क, खुले स्थल एवं हरित पट्टिका भूमि की सम्यक पहचान, उनके संरक्षण, उक्त भूमि पर हो रहे अवैध एवं अनधिकृत निर्माणों की प्रभावी रोकथाम, तथा पूर्व में की गई पर्यावरणीय क्षति के पुनर्स्थापन हेतु, मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 05.02.2019 का अक्षरशः, प्रभावी एवं समयबद्ध अनुपालन कराया जाना अत्यंत आवश्यक है, जिससे महायोजनाओं की वैधानिक मंशा की रक्षा हो सके तथा पर्यावरणीय संतुलन एवं सार्वजनिक हित सुनिश्चित किया जा सके।

5. That for the purpose of proper identification of land earmarked as parks, open spaces and green belts in the Master Plan, for their protection, for effective prevention of illegal and unauthorized constructions on such land, and for restoration of environmental damage already caused, it is extremely necessary that the Government Order dated 05.02.2019 issued by the Government of Uttar Pradesh, in compliance of the orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal, be implemented **strictly, effectively and in a time-bound manner**, so that the statutory intent of the Master Plans is safeguarded and environmental balance as well as public interest are duly ensured.

6. **यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 8, 9 एवं 10 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में किए गए कथन अपूर्ण, तथ्यहीन, असत्य, मनगढ़ंत एवं भ्रामक हैं,** जिन्हें आवेदक पूर्णतः अस्वीकार करता है। उक्त कथन न तो अभिलेखीय साक्ष्यों से समर्थित हैं और न ही विधिक कसौटी पर खरे उतरते हैं, अतः वे माननीय न्यायाधिकरण द्वारा भी अस्वीकार किए जाने योग्य हैं। इन तथ्यों की वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने हेतु आवेदक निम्नलिखित तथ्यों को प्रस्तुत कर रहा है:–

6. **That the statements made in the reply submitted by Respondent Nos. 1, 3, 4, 8, 9 and 10 are incomplete, baseless, false,** fabricated and misleading, which are wholly

denied by the Applicant. The said statements are neither supported by documentary evidence nor do they stand the test of law; therefore, they are also liable to be rejected by the Hon'ble Tribunal. In order to clarify the true and factual position of the matter, the Applicant is placing the following facts on record:–

A. यह कि प्रतिवादी संख्या–4 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर प्रत्युत्तर दिनांक 04.11.2024 (अभिलेख सं. 92-97) एवं प्रत्युत्तर दिनांक 24.02.2025 (अभिलेख सं. 143-149) अत्यंत औपचारिक, अपूर्ण एवं वास्तविक तथ्यों से परे है। यह स्वीकारोक्ति स्वयं UPPCB द्वारा की गई है कि दिनांक 25.10.2024 एवं 27.01.2025 (अभिलेख सं. 148-149) को जिला वन अधिकारी, झांसी तथा झांसी विकास प्राधिकरण को पत्र प्रेषित किया गया, किन्तु उसके अनुपालन में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, जिससे स्पष्ट है कि संबंधित विभागों द्वारा अवैध निर्माण, वृक्ष कटान एवं पहाड़ियों को क्षति पहुँचाने जैसे गंभीर पर्यावरणीय उल्लंघनों पर कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। इसके अतिरिक्त, UPPCB द्वारा दिनांक 29.10.2024 को की गई स्थल निरीक्षण कार्यवाही केवल औपचारिक रही, क्योंकि स्वयं बोर्ड ने यह स्वीकार किया है कि "निर्माण की स्थिति के संबंध में विशिष्ट जानकारी के अभाव में" कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सका। यह स्थिति UPPCB की वैधानिक जिम्मेदारियों के निर्वहन में घोर लापरवाही को दर्शाती है, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं जल/वायु अधिनियमों के अंतर्गत UPPCB पर यह दायित्व है कि वह स्वतः संज्ञान लेकर प्रभावी जांच, दोषियों की पहचान तथा दंडात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करे। अतः UPPCB का यह प्रत्युत्तर न तो आवेदक के गंभीर आरोपों का खंडन करता है और न ही माननीय अधिकरण के आदेशों के अनुपालन को दर्शाता है, बल्कि यह पर्यावरणीय क्षति को रोकने में प्रशासनिक विफलता को उजागर करता है।

A. It is respectfully submitted that the counter-affidavit filed by the Respondent Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) dated 04.11.2024 (Records No. 92-97) and dated 24.02.2025 (Records No. 143-149) is highly formalistic, incomplete, and detached from the actual facts. UPPCB itself admits that a letter was sent on dated 25.10.2024 and 27.01.2025 (Records No. 148-149) to the District Forest Officer, Jhansi, and the Jhansi Development Authority, but no response was received in compliance thereof. This clearly indicates that the concerned authorities failed to take any effective action against serious environmental violations such as unauthorized constructions, tree felling, and damage to the hills. Further, the site inspection conducted by UPPCB on 29.10.2024 was merely formal, as the Board itself admitted that no conclusive findings could be drawn "due to the lack of specific information regarding the status of construction". This demonstrates gross negligence on the part of UPPCB in discharging its statutory responsibilities, as under the Environment Protection Act, 1986 and other related water and air laws, UPPCB is obligated to take suo motu cognizance, conduct effective investigation, identify offenders, and ensure punitive action. Therefore, the reply of UPPCB neither refutes the serious allegations made by the applicant nor demonstrates compliance with the orders of the Hon'ble Tribunal, but rather exposes administrative failure in preventing environmental damage.

B. यह कि प्रतिवादी संख्या–10 नगर निगम झांसी द्वारा अपने प्रत्युत्तर दिनांक 22.02.2025 (अभिलेख सं. 101-142) में भूमि के सीमांकन विवाद, निजी भूमिधर अधिकार तथा माननीय उच्च न्यायालय में

लंबित वादों का हवाला देकर अपने दायित्व से बचने का प्रयास किया गया है, जो विधि एवं तथ्य दोनों दृष्टि से अस्वीकार्य है, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण पर्यावरणीय क्षति, हरित क्षेत्र के संरक्षण, अवैध निर्माण एवं वृक्षों की अवैध कटान से संबंधित है, न कि मात्र भूमि स्वामित्व के निर्धारण से; यह स्थापित विधि है कि किसी भूमि पर न्यायालयीन विवाद लंबित होने मात्र से पर्यावरण संरक्षण, अतिक्रमण रोकने एवं वैधानिक निगरानी की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती, विशेषकर तब जब स्वयं प्रतिवादी स्वीकार करता है कि विवादित भूमि का एक बड़ा भाग राजस्व अभिलेखों के अनुसार झांसी नगर निगम के प्रबंधन एवं नियंत्रण में है; अतः सीमांकन विवाद अथवा निजी भूमि का बहाना बनाकर अवैध निर्माण, अतिक्रमण एवं पर्यावरणीय उल्लंघन पर कार्यवाही न करना स्पष्ट रूप से वैधानिक कर्तव्यों के उल्लंघन के समान है; साथ ही, यह भी उल्लेखनीय है कि नगर निगम अधिनियम एवं पर्यावरणीय कानूनों के अंतर्गत प्रतिवादी संख्या–10 का यह दायित्व है कि वह अपने क्षेत्राधिकार में स्थित भूमि पर अवैध गतिविधियों को रोके, निगरानी रखे एवं पर्यावरणीय क्षति को तत्काल रोके, चाहे भूमि का स्वामित्व अंतिम रूप से किसी के पक्ष में तय हुआ हो या नहीं; अतः प्रतिवादी द्वारा मूल आवेदन को अपोषणीय व समयबाह्य बताना निराधार, भ्रामक एवं तथ्य-विरुद्ध है तथा माननीय अधिकरण द्वारा इसे अस्वीकार किए जाने योग्य है।

B. It is respectfully submitted that the counter-affidavit filed by Respondent No. 10 dated 22.02.2025 (Records No. 101-142) attempts to evade its statutory responsibilities by citing land demarcation disputes, private landholding rights, and pending cases before the Hon'ble High Court. Such a defense is legally and factually untenable, as the matter before the Hon'ble National Green Tribunal pertains to environmental damage, protection of green areas, unauthorized constructions, and illegal tree felling, and not merely the determination of land ownership. It is well-settled law that the mere pendency of judicial disputes over a piece of land does not absolve the authorities from their statutory duty to protect the environment, prevent encroachments, and exercise lawful supervision, especially when the respondent itself admits that a significant portion of the disputed land is under the management and control of Jhansi Municipal Corporation as per revenue records. Accordingly, using demarcation disputes or private ownership as a pretext for inaction regarding unauthorized constructions, encroachments, and environmental violations constitutes a clear breach of statutory obligations. Furthermore, it is pertinent to note that under the Municipal Corporation Act and applicable environmental laws, Respondent No. 10 is duty-bound to prevent illegal activities, monitor its jurisdictional land, and take immediate steps to avert environmental harm, irrespective of the final determination of ownership. Therefore, the respondent's contention that the original application is non-maintainable and barred by limitation is baseless, misleading, and contrary to the facts, and is liable to be rejected by the Hon'ble Tribunal.

C. यह कि प्रतिवादी संख्या–4 उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 24.02.2025 (अभिलेख सं. 143-149) केवल औपचारिकता की पूर्ति मात्र है तथा इससे यह स्पष्ट रूप से सिद्ध होता है कि बोर्ड ने माननीय अधिकरण के आदेश दिनांक 06.11.2024 के बावजूद न तो स्वयं कोई प्रभावी जांच की और न ही प्रदूषण नियंत्रण अधिनियमों के अंतर्गत अपने वैधानिक अधिकारों का

प्रयोग करते हुए कोई ठोस कार्यवाही की। प्रत्युत्तर के पैरा 7 एवं 9 से यह स्वीकारोक्ति स्पष्ट है कि बोर्ड कथित अवैध निर्माणों एवं व्यापक स्तर पर वृक्ष कटान की स्थिति का सत्यापन करने में विफल रहा तथा अन्य विभागों से उत्तर न मिलने को बहाना बनाकर स्वयं अपनी वैधानिक जिम्मेदारी से बचने का प्रयास किया गया। यह स्थापित विधि है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एक स्वतंत्र वैधानिक प्राधिकरण है, जिसे पर्यावरण संरक्षण हेतु निरीक्षण, कारण बताओ नोटिस जारी करने, निर्माण/गतिविधियों पर रोक लगाने तथा अभियोजन की संस्तुति करने के व्यापक अधिकार प्राप्त हैं, जिन्हें प्रयोग में न लाना स्वयं में आदेशों की अवहेलना एवं पर्यावरणीय क्षति को मौन स्वीकृति प्रदान करने के समान है। अतः यह प्रत्युत्तर असंतोषजनक, अपूर्ण एवं पर्यावरणीय कानूनों की भावना के विपरीत है तथा माननीय अधिकरण से प्रार्थना है कि बोर्ड को स्वतंत्र एवं समयबद्ध स्थल निरीक्षण, उत्तरदायित्व निर्धारण तथा कठोर वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया जाए।

C. It is respectfully submitted that the counter-affidavit filed by the Uttar Pradesh Pollution Control Board (UPPCB) dated 24.02.2025 (Records No. 143-149) is merely a formalistic compliance and clearly demonstrates that, despite the Hon'ble Tribunal's order dated 06.11.2024, the Board neither conducted any effective investigation on its own nor exercised its statutory powers under the Pollution Control Acts to take concrete action. The admissions in paragraphs 7 and 9 of the reply clearly indicate that the Board failed to verify the status of the alleged unauthorized constructions and widespread tree felling, and attempted to evade its statutory responsibility by taking refuge in the non-response from other departments. It is well-established law that the UPPCB is an independent statutory authority vested with wide-ranging powers to inspect, issue show-cause notices, halt constructions/activities, and recommend prosecution for environmental violations. Failure to exercise these powers amounts to disobedience of orders and tacit approval of environmental harm. Accordingly, the counter-affidavit is unsatisfactory, incomplete, and contrary to the spirit of environmental laws, and it is respectfully prayed that the Hon'ble Tribunal may direct the Board to undertake independent, time-bound site inspections, determine responsibilities, and take stringent statutory action forthwith.

D. यह कि प्रतिवादी संख्या–3 की ओर से डी.एफ.ओ. झांसी द्वारा प्रस्तुत उत्तर दिनांक 26.02.2025 (अभिलेख सं. 150-157) से यह तथ्य स्वयं सिद्ध होता है कि विवादित स्थल पर अवैध रूप से वृक्षों का कटान किया गया है, जिसके संबंध में वन विभाग द्वारा जांच कर प्रकरण भी पंजीकृत किया गया है, तथा यह भी निर्विवाद रूप से स्वीकार किया गया है कि किसी भी विभाग अथवा संस्था द्वारा उक्त स्थल पर वृक्ष कटान हेतु वन विभाग से कोई अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। यह प्रतिवादी का उत्तर आवेदक द्वारा लगाए गए आरोपों की पुष्टि करता है कि प्रस्तावित प्रखंडीय पार्क क्षेत्र में पर्यावरणीय क्षति पहुंचाई गई है। मात्र यह कहना कि भूमि वन भूमि के रूप में अभिलेखित नहीं है, पर्यावरण संरक्षण के दायित्व से प्रतिवादियों को मुक्त नहीं करता, क्योंकि उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, 1976 के अंतर्गत किसी भी भूमि पर बिना अनुमति वृक्षों का कटान दंडनीय अपराध है। अतः प्रतिवादी संख्या–3 का उत्तर पर्यावरणीय उल्लंघन को स्वीकार करने के समान है और इससे यह स्पष्ट होता है कि संबंधित प्राधिकरणों की निष्क्रियता एवं आपसी समन्वय के अभाव में अवैध वृक्ष कटान एवं निर्माण गतिविधियाँ की गईं, जिस पर माननीय अधिकरण का हस्तक्षेप एवं कठोर निर्देश अत्यंत आवश्यक है।

D. That it is respectfully submitted that the reply filed by Respondent No. 3 dated 26.02.2025 (at pages 150–157 of the record) itself conclusively establishes the fact that illegal felling of trees has taken place at the disputed site. It has been categorically admitted therein that the Forest Department conducted an investigation into the matter and a case has also been registered in rela P.T.O. 08 said illegal tree felling. It has further been unequivocally admitted that no department or institution had obtained any permission from the Forest Department for felling of trees at the said site. That the said reply of Respondent No. 3, therefore, clearly corroborates and substantiates the allegations made by the Applicant that environmental damage has been caused in the area proposed for the Prakhandiya Park. Merely stating that the land is not recorded as forest land does not absolve the Respondents of their statutory and constitutional obligation to protect the environment, as under the Uttar Pradesh Tree Protection Act, 1976, felling of trees on any land without prior permission is a punishable offence. Thus, the reply of Respondent No. 3 amounts to an admission of environmental violations, and it clearly reflects that due to the inaction, negligence, and lack of inter-departmental coordination on the part of the concerned authorities, illegal tree felling and construction activities were allowed to take place at the disputed site. In view of the above, the intervention of this Hon'ble Tribunal and issuance of strict directions is absolutely necessary to prevent further environmental degradation and to enforce the rule of law.

E. यह कि प्रतिवादी संख्या-9, झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 19.08.2025 (अभिलेख सं. 350-457) तथ्यात्मक रूप से भ्रामक, विधिक रूप से अस्थिर तथा माननीय अधिकरण को गुमराह करने वाला है। केवल इस आधार पर कि आवेदक ने प्रारंभिक आवेदन में खसरा संख्या अंकित नहीं की, अवैध निर्माणों, हरित क्षेत्र/पार्क हेतु आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण तथा पर्यावरणीय क्षति से पल्ला झाड़ना स्वीकार्य नहीं है, विशेषकर तब जब मास्टर प्लान–2021 के अंतर्गत क्षेत्र के भू-उपयोग का निर्धारण प्राधिकरण के अभिलेखों में स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। यह स्वीकारोक्ति कि उक्त क्षेत्र निजी भूमि है, प्रतिवादी संख्या-9 को मास्टर प्लान एवं विकास नियंत्रण विनियमों के उल्लंघन के विरुद्ध कार्यवाही से मुक्त नहीं करती, क्योंकि निजी भूमि पर भी मास्टर प्लान के विपरीत निर्माण पूर्णतः निषिद्ध है। मास्टर प्लान–2031 का संदर्भ देकर पूर्व में स्वीकृत मास्टर प्लान–2021 के तहत आरक्षित हरित क्षेत्र के संरक्षण संबंधी दायित्व से स्वयं को मुक्त करना कानूनन असंगत है। तथाकथित 13 अवैध निर्माणों पर की गई कार्यवाही का कोई ठोस विवरण, दिनांक, स्थल अथवा परिणाम प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे प्रतिवादी संख्या-9 की निष्क्रियता एवं कर्तव्यच्युतता स्पष्ट होती है। अतः प्रतिवादी संख्या-9 का प्रत्युत्तर अस्वीकार्य है तथा माननीय अधिकरण से निवेदन है कि स्वतंत्र जांच कराते हुए अवैध निर्माणों एवं पर्यावरणीय उल्लंघनों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के निर्देश पारित किए जाएं।

E. That it is respectfully submitted that the reply filed by Respondent No. 9 – Jhansi Development Authority, dated 19.08.2025 (at pages 350–457 of the record), is factually misleading, legally untenable, and calculated to mislead this Hon'ble Tribunal. Merely on the ground that the Applicant did not mention the khasra numbers in the original application, the Respondent No. 9 cannot evade its statutory responsibility with respect to illegal constructions, encroachments upon

land reserved for green area/park, and the resultant environmental degradation, particularly when the land-use demarcation under the Master Plan–2021 is clearly available in the official records of the Authority itself. That the admission of Respondent No. 9 that the area in question comprises private land does not absolve it from taking action against violations of the Master Plan and Development Control Regulations, as construction contrary to the Master Plan is strictly prohibited even on private land. The attempt of Respondent No. 9 to rely upon the Master Plan–2031 to escape its obligations towards protection of green areas reserved under the duly sanctioned Master Plan–2021 is legally impermissible and wholly misconceived. That the bald assertion regarding action taken against 13 alleged unauthorized constructions is unsupported by any cogent material, particulars, dates, site details, or outcomes, which clearly demonstrates the inaction, dereliction of duty, and failure of Respondent No. 9 to discharge its statutory functions. In view of the foregoing, the reply of Respondent No. 9 deserves to be rejected, and this Hon'ble Tribunal may be pleased to direct an independent inquiry and to pass strict directions for initiation of coercive action against illegal constructions and environmental violations, in order to uphold the rule of law and protect the environment.

F. यह कि प्रतिवादी संख्या-1, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) द्वारा दायर काउंटर एफिडेविट दिनांक 29.07.2025 (अभिलेख सं. 158-335) मुख्यतः पर्यावरण प्रभाव आंकलन अधिसूचना, 2006 से संबंधित सामान्य कानूनी प्रावधानों, अधिसूचनाओं एवं माननीय उच्चतम न्यायालय/राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों के उल्लेख तक ही सीमित है, जबकि वर्तमान वाद में उठाया गया मूल प्रश्न झांसी मास्टर प्लान-2021 के अंतर्गत प्रस्तावित प्रखंडिया पार्क (हरित क्षेत्र) में हो रही वास्तविक, स्थल-विशिष्ट एवं निरंतर पर्यावरणीय क्षति, अवैध वृक्ष कटान तथा बिना किसी वैधानिक स्वीकृति के किए जा रहे नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, वाणिज्यिक एवं आवासीय निर्माणों से संबंधित है। MoEF&CC द्वारा यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उक्त निर्माण कार्यों के संबंध में किसी प्रकार की पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) प्राप्त की गई है अथवा नहीं, अथवा किसी उल्लंघन की स्थिति में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के अंतर्गत कोई दंडात्मक या निरोधात्मक कार्यवाही की गई है। केवल यह कहना कि कुछ विषय राज्य स्तरीय प्राधिकरणों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, केंद्रीय मंत्रालय को उसके पर्यवेक्षणीय एवं वैधानिक दायित्वों से मुक्त नहीं करता, विशेषकर तब जब माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Ex-post facto पर्यावरणीय स्वीकृतियों पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया जा चुका है। अतः प्रतिवादी संख्या-1 का प्रत्युत्तर अपूर्ण, औपचारिक एवं तथ्यात्मक अनुपालन से रहित है और यह निवेदन है कि माननीय अधिकरण MoEF&CC को राज्य प्राधिकरणों के साथ समन्वय स्थापित कर स्थल-विशिष्ट जांच, उल्लंघन की पहचान तथा पर्यावरणीय क्षति के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण हेतु ठोस निर्देश जारी करे।

F. It is respectfully submitted that the counter-affidavit filed by Respondent No. 1, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC) dated 29.07.2025 (Records No. 158-335) primarily addresses general legal provisions, notifications, and references to the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006, as well as orders of the Hon'ble Supreme Court and the National Green Tribunal. However, the principal issue raised in the present

matter relates to the actual, site-specific, and ongoing environmental degradation, illegal tree felling, and unauthorized construction of nursing homes, pathology labs, commercial, and residential buildings within the proposed Block Park (green area) under the Jhansi Master Plan-2021. The MoEF&CC has failed to clarify whether any environmental clearance (EC) has been obtained for the aforementioned constructions, or whether any punitive or restraining action has been taken under the Environment (Protection) Act, 1986 in case of violations. The mere assertion that certain matters fall within the jurisdiction of State-level authorities does not absolve the Central Ministry from its supervisory and statutory responsibilities, particularly when the Hon'ble Supreme Court has expressly prohibited ex-post facto environmental clearances. Accordingly, the counter-affidavit of Respondent No. 1 is incomplete, formalistic, and devoid of factual compliance, and it is respectfully prayed that the Hon'ble Tribunal may direct the MoEF&CC to coordinate with the State authorities, undertake site-specific inspections, identify violations, and determine accountability for environmental harm.

G. यह कि प्रतिवादी संख्या-8, जिला मजिस्ट्रेट, झांसी की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर दिनांक 12.11.2025 (अभिलेख सं. 489-490) मात्र औपचारिकता निभाने तक सीमित है तथा उसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिनांक 29.05.2025 के आदेश के वास्तविक, प्रभावी एवं समयबद्ध अनुपालन का कोई ठोस विवरण नहीं दिया गया है। समिति के गठन एवं पत्राचार का उल्लेख किए जाने के बावजूद न तो स्थल निरीक्षण की कोई निष्कर्षात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और न ही प्रस्तावित प्रखंडिया पार्क, जो कि झांसी मास्टर प्लान–2021 के अंतर्गत हरित क्षेत्र के रूप में आरक्षित है, में हुए अवैध निर्माणों एवं वृक्षों की अवैध कटान के संबंध में किसी प्रकार की दंडात्मक अथवा निरोधात्मक कार्यवाही का उल्लेख किया गया है। केवल यह कहना कि झांसी विकास प्राधिकरण से रिपोर्ट अपेक्षित है, जिला प्रशासन को उसके संवैधानिक एवं वैधानिक दायित्वों से मुक्त नहीं करता, विशेषकर तब जब पर्यावरणीय क्षति सतत रूप से जारी हो। अतः प्रतिवादी जिला प्रशासन की निष्क्रियता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है और यह माननीय अधिकरण के आदेशों की अवहेलना के समान है; इसलिए निवेदन है कि जिला मजिस्ट्रेट, झांसी को ठोस, समयबद्ध एवं परिणामोन्मुख कार्यवाही कर विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया जाए।

G. It is respectfully submitted that the reply submitted by the District Magistrate, Jhansi dated 12.11.2025 (Records No. 489-490) is limited merely to formal compliance and does not provide any concrete details regarding the actual, effective, and time-bound implementation of the Hon'ble National Green Tribunal's order dated 29.05.2025. Despite mentioning the formation of a committee and correspondence, no conclusive site inspection report has been submitted, nor has any punitive or restraining action been taken concerning the unauthorized constructions and illegal tree felling in the proposed Prakhandiya Park, which is reserved as a green area under the Jhansi Master Plan–2021. The mere assertion that a report is awaited from the Jhansi Development Authority does not absolve the District Administration of its constitutional and statutory obligations, particularly when environmental damage continues unabated.

Therefore, the inaction of the District Administration is evident and amounts to non-compliance with the orders of the Hon'ble Tribunal. It is respectfully prayed that the Hon'ble Tribunal may direct the District Magistrate, Jhansi to take concrete, time-bound, and result-oriented action and submit a detailed compliance report.

7. यह कि झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी द्वारा इस संपूर्ण प्रकरण में अपनाया गया आचरण केवल साधारण प्रशासनिक लापरवाही न होकर, माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेशों की जानबूझकर, निरंतर एवं सोची-समझी अवहेलना को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। माननीय अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.07.2024, 06.11.2024 एवं 29.05.2025 में पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील भूमि, प्रस्तावित प्रखण्डीय पार्क क्षेत्र, पहाड़ी भू-भाग एवं वृक्षों की अवैध कटान पर तत्काल प्रभाव से रोक, स्थल निरीक्षण, तथ्यात्मक स्थिति स्पष्ट करने तथा अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, किंतु झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा आज तक न तो कोई प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया गया और न ही किसी प्रकार की ठोस प्रवर्तनात्मक कार्यवाही की गई।

7. That the conduct adopted by the Jhansi Development Authority, Jhansi in the present matter is not merely an instance of ordinary administrative negligence, but clearly demonstrates a wilful, continuous and deliberate disobedience of the orders passed by the Hon'ble National Green Tribunal, New Delhi. The Hon'ble Tribunal, vide its orders dated 30.07.2024, 06.11.2024 and 29.05.2025, had issued clear directions for immediate restraint on illegal constructions, hill cutting and illegal felling of trees in the environmentally sensitive land, proposed Prakhandiya Park area and hilly terrain, as well as for site inspection, clarification of the factual position and initiation of action against illegal constructions. However, till date, the Jhansi Development Authority has neither ensured any effective compliance nor taken any concrete enforcement action whatsoever.

8. यह कि उप जिलाधिकारी (न्यायिक), झांसी द्वारा आदेश संख्या 494 दिनांक 19.08.2025 के माध्यम से संयुक्त टीम गठन, स्थल निरीक्षण एवं वास्तविक स्थिति की रिपोर्टिंग हेतु स्पष्ट निर्देश जारी किए गए, तथापि झांसी विकास प्राधिकरण ने उक्त आदेशों के अनुपालन में भी घोर उदासीनता, शिथिलता एवं निष्क्रियता प्रदर्शित की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्राधिकरण ने अपने वैधानिक दायित्वों का निर्वहन जानबूझकर नहीं किया। यह आचरण न केवल प्रशासनिक अनुशासनहीनता है, बल्कि माननीय अधिकरण एवं सक्षम राजस्व अधिकारियों के आदेशों को निष्प्रभावी करने का प्रयास भी है।

8. That the Sub-Divisional Magistrate (Judicial), Jhansi, vide Order No. 494 dated 19.08.2025, issued specific directions for constitution of a joint team, site inspection and submission of a factual status report; however, the Jhansi Development Authority displayed gross indifference, laxity and inaction even in complying with the said order, which clearly shows that the Authority has deliberately failed to discharge its statutory duties. Such conduct amounts not only to administrative indiscipline but also to an attempt to render ineffective the orders passed by the Hon'ble Tribunal and the competent revenue authorities.

9. यह कि झांसी विकास प्राधिकरण, जो कि उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत नियोजन, नियंत्रण एवं अवैध निर्माणों पर रोक लगाने हेतु विधिक रूप से उत्तरदायी प्राधिकरण है, द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करना तथा उत्तर प्रदेश पार्क, खेल के मैदान और खुले स्थान (संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 1975 के प्रावधानों की अवहेलना करना, कानून के शासन (Rule of Law) पर सीधा प्रहार है। प्राधिकरण की इस निरंतर निष्क्रियता के कारण ही पर्यावरणीय रूप से संरक्षित भूमि पर अवैध नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, व्यावसायिक मेडिकल स्टोर एवं आवासीय निर्माण फल-फूल रहे हैं और वृक्षों एवं पहाड़ियों की अवैध कटान बिना किसी भय के जारी है।

9. That the Jhansi Development Authority, being a statutory authority legally responsible for planning, regulation and prevention of illegal constructions under the Uttar Pradesh Nagar Yojana Evam Vikas Adhiniyam, 1973, has failed to discharge its statutory obligations, and has also violated the provisions of the Uttar Pradesh Park, Khel Ke Maidan Aur Khule Sthan (Sanrakshan Evam Viniyaman) Adhiniyam, 1975, thereby striking at the very root of the Rule of Law. Due to such continued inaction on the part of the Authority, illegal nursing homes, pathology centres, commercial medical stores and residential constructions are flourishing on environmentally protected land, and illegal cutting of trees and hills is continuing unabated without any fear of law.

10. यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पत्र संख्या 502/OA-485/24 दिनांक 25.10.2024 एवं तत्पश्चात पत्र संख्या 108/OA-485/NGT/25 दिनांक 27.01.2025 के माध्यम से झांसी विकास प्राधिकरण से बार-बार स्थल से संबंधित सूचनाएं, अभिलेख एवं की गई कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया, किंतु झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 29.10.2024 के स्थल निरीक्षण में भी वास्तविक स्थिति की पुष्टि संभव नहीं हो सकी, जैसा कि स्वयं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अभिलेखों में स्वीकार किया गया है। यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि झांसी विकास प्राधिकरण ने तथ्यों को छिपाकर माननीय अधिकरण की न्यायिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष बाधा उत्पन्न की है।

10. hat the Regional Office of the Uttar Pradesh Pollution Control Board, vide Letter No. 502/OA-485/24 dated 25.10.2024 and thereafter vide Letter No. 108/OA-485/NGT/25 dated 27.01.2025, repeatedly requested the Jhansi Development Authority to provide site-related information, relevant records and details of action taken. However, the Jhansi Development Authority deliberately failed to provide any information whatsoever, as a result of which even during the site inspection conducted on 29.10.2024, the actual factual position could not be verified, as has been admitted by the Pollution Control Board itself on record. This clearly establishes that the Jhansi Development Authority has suppressed material facts and has caused direct obstruction in the judicial proceedings before the Hon'ble Tribunal.

11. यह कि क्षेत्रीय कार्यालय, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा उप जिलाधिकारी (न्यायिक), झांसी द्वारा समय-समय पर विधिवत पत्राचार एवं आदेशों के माध्यम से झांसी विकास प्राधिकरण से स्थल से संबंधित आवश्यक सूचनाएं, प्रासंगिक अभिलेख तथा की गई/प्रस्तावित कार्यवाही का विवरण उपलब्ध कराए जाने का बार-बार अनुरोध किया गया, किंतु झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त वैधानिक अनुरोधों की पूर्णतः उपेक्षा करते हुए कोई भी सूचना अथवा अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया गया, जो कि प्राधिकरण की गंभीर

लापरवाही, जानबूझकर की गई आदेश-अवहेलना, कर्तव्यहीनता एवं माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण की न्यायिक प्रक्रिया में प्रत्यक्ष बाधा उत्पन्न करने वाला आचरण है।

11. That the Regional Office of the Uttar Pradesh Pollution Control Board as well as the Sub-Divisional Magistrate (Judicial), Jhansi, from time to time, through duly issued correspondence and orders, repeatedly requested the Jhansi Development Authority to furnish necessary site-related information, relevant records and details of action taken/proposed to be taken; however, the Jhansi Development Authority completely ignored such statutory requests and failed to provide any information or records, which constitutes grave negligence, wilful disobedience of orders, dereliction of duty and conduct amounting to direct interference with and obstruction of the judicial process of the Hon'ble National Green Tribunal.

12. यह कि आवेदक डॉ. अजय कुमार की ओर से प्रेषित प्रतिउत्तर दिनांक 10.11.2025 के अतिरिक्त कथन के पैराग्राफ संख्या 12 से 28 में, राज्य शासन द्वारा जारी विभिन्न शासनादेशों तथा उन शासनादेशों के अनुक्रम में अनिवार्य कार्यवाहियों के पालन न किए जाने के गंभीर तथ्यों का विस्तृत रूप से खुलासा किया गया है। उक्त अतिरिक्त कथन में यह स्पष्ट दर्शाया गया है कि संबंधित प्राधिकरणों एवं उत्तरदायी अधिकारियों द्वारा शासनादेशों के स्पष्ट, बाध्यकारी एवं वैधानिक निर्देशों की निरंतर अवहेलना की गई है। उक्त अतिरिक्त कथन के पैराग्राफ का अंग्रेज़ी अनुवाद निम्नवत है।

12. That in the additional statements contained in paragraphs 12 to 28 of the rejoinder dated 10.11.2025 submitted on behalf of the Applicant, Dr. Ajay Kumar, serious facts have been elaborately disclosed regarding the various Government Orders issued by the State Government and the non-compliance of the mandatory actions required to be taken pursuant to those Government Orders. The said additional statements clearly demonstrate that the concerned authorities and responsible officers have continuously disregarded the clear, binding and statutory directions contained in the Government Orders. The English translation of the said paragraphs of the additional statements is as under.

12. That in the Jhansi Master Plan–2001 approved by the State Government, 39 revenue villages comprising an area of 5002.90 hectares were included. The said Master Plan was approved vide Government Order No. 4201/37-3-82-32-N.K.V./81 dated 13.10.1982, in which the aforesaid Sectoral Park includes the villages Pichhor, Kochhabhanwar and Karguwan.

13. That in the Jhansi Master Plan–2021 approved by the State Government, the aforesaid revenue villages have been retained as such. The said Master Plan was approved vide Government Order No. 5091/8-A-3-2004-11-Maha/2000 T.C. dated 20.12.2004, in which the aforesaid Sectoral Park includes the villages Pichhor, Kochhabhanwar and Karguwan.

14. That a few months ago, the Jhansi Development Authority uploaded on its website Sajra Sheets and vague and incomplete details of land use village-wise for a total of 20 revenue villages, which include the villages Pichhor, Kochhabhanwar and Karguwan pertaining to the aforesaid Sectoral Park, which are annexed herewith.

15. That on page no. 5, paragraph no. 5 of the Original Application, Government Order "(2) No. W-09/8-3-19-206 Misc./2018 T.C. dated 16.01.2019" has been mentioned, whereby the Government directed that as per the land use indicated in the Master Plan, the details of land as per revenue records including Gata numbers, Khasra numbers and Arazi numbers be made available immediately to the District Magistrate / Stamp and Registration Department of the district. It was further directed that immediate surveys be conducted to stop constructions carried out against the land use of Green Belts and Parks earmarked in the Master Plans within the jurisdiction of Development Authorities,

and action be taken against such constructions in accordance with law. However, till date no action whatsoever has been taken by the Jhansi Development Authority in this regard. Despite the clear and mandatory directions of the aforesaid Government Order, no effective action has been taken by the Jhansi Development Authority till date, which reflects gross negligence in the discharge of duties by the Vice Chairman, Jhansi Development Authority.

16. That as per the directions contained in Government Order No. 168/8-3-20-206 Misc./18-T.C. dated 19.02.2020, as mentioned on page no. 5, paragraph no. 5 of the Original Application, the State Government clearly ordered that: The Development Authorities and regulated area authorities shall prepare details of Gata numbers/Khasra numbers/Arazi numbers of lands reserved for public use such as Parks, Open Spaces, Green Belts, Playgrounds and Master Plan roads as proposed in the effective Master Plans, and shall publicly display/upload the said details on the official website of the concerned development agency by superimposing them on the Sajra maps, and shall also immediately provide the said details to the district-level Stamp and Registration Department, so as to prevent any illegal transfer, sale, construction or change of land use on such reserved lands.

However, it is an extremely serious and regrettable fact that despite several years having elapsed since the issuance of the aforesaid Government Order, till date the Jhansi Development Authority has neither prepared the said details, nor published them on its website, nor provided them to the Stamp and Registration Department. Thus, the respondent authority is in complete disregard of the legal directions of the State Government, which is not only contrary to the orders of the State Government but is also against public interest and the principles of environmental protection.

Therefore, in the interest of environmental protection and justice, it is extremely necessary that the Hon'ble Tribunal direct the Jhansi Development Authority as under:

(a) To make publicly available on its official website within a stipulated period, in compliance with the Government Order dated 19.02.2020, complete details of all Gata/Khasra/Arazi numbers related to parks, open spaces, green belts, sectoral parks and Master Plan roads reserved in the Jhansi Master Plan, along with superimposed live maps.

(b) To immediately provide copies of the aforesaid records and maps to the District Stamp and Registration Office, so as to ensure compliance with legal restrictions on registration/sale/transfer of reserved land.

(c) To ensure fixation of accountability and necessary disciplinary action in accordance with law against the responsible officers of the Jhansi Development Authority for long-term non-compliance of the Government Order.

17. That on page no. 5, paragraph no. 5 of the Original Application, reference has been made to the Government Orders issued in compliance with the directions passed by the Hon'ble Tribunal in OA No. 380 of 2018, whereby directions were issued to impose a ban on sale and purchase of land falling within parks, open spaces, green belts and playgrounds reserved in the effective Master Plans, and to conduct surveys to stop/remove unauthorized/illegal constructions and encroachments therein. Due to non-compliance with the said Government Orders, Shri Narendra Kushwaha filed OA No. 114 of 2021 to ensure compliance of the said orders and Government Orders, wherein the Hon'ble Tribunal directed that, *"in the first instance, by the Principal Secretary, Urban Development, UP and remedial action be taken in accordance with law. Ordered accordingly."* The said direction has also not been complied with till date.

18. That the State Government of Uttar Pradesh issued Government Order No. 2079/8-1-11-35 Misc./2011 dated 23.06.2011, under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, issuing directions regarding the role, objectives and duties of Development Authorities in urban planning and development, which is annexed herewith.

19. That in the aforesaid Government Order dated 23.06.2011, on page 3, paragraph 2.2, sub-paragraphs (1) to (6), powers and authority have been conferred upon the Development Authority to stop, remove and seal constructions made without permission as specified in the Master Plan or under Section 14 of the Act, or in violation of any condition, and to discharge various duties under Sections 25, 26, 26-A, 27, 28 and 28-A of the Act. The said provisions are not being complied with by the Jhansi Development Authority.

20. That in the aforesaid Government Order dated 23.06.2011, on page 6, paragraph 2.4, sub-paragraph (c), directions have been issued for environmental protection by way of plantation, protection of green areas, ponds, water bodies, etc., and promotion of the use of non-conventional

energy sources, and in sub-paragraph (d), to make the general public aware of Government policies, directions and Government Orders.

21. That the State Government of Uttar Pradesh issued Government Order No. 1428/8-8-2018-194 Comp./2001 dated 09.08.2018, issuing directions for effective control and prevention of unauthorized colonies, wherein instructions have been issued to lodge FIRs and take stringent action against illegal constructions, illegal colonies, their builders, and the officers/personnel who are guilty of failure or involvement in preventing the same.

22. That the officers of the Jhansi Development Authority are acting in a manner contrary to the dignity of their constitutional and administrative positions and are providing protection and encouragement to illegal constructions. This directly amounts to violation of the provisions of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, the Parks Land Protection Act, 1975 and the Environment (Protection) Act, 1986, which is a serious punishable offence.

23. That widespread complaints of large-scale corruption have been received in relation to illegal constructions on park land, wherein it has been clearly alleged that the officers of the Authority are continuously assisting unauthorized constructions on green belts, sectoral parks and public land by taking bribes for personal gain.

24. That the reply submitted by Respondent No. 9 before the Hon'ble Tribunal is false, misleading and based on fabricated facts. An analysis of the said reply reveals that most of the facts stated therein have no valid or authentic documentary basis, which clearly establishes that the reply is defective from both moral and legal perspectives.

25. That administrative protection has been provided for illegal constructions on land reserved for parks, green areas and public places in the Jhansi Master Plan. Despite the orders of the Hon'ble Supreme Court, Hon'ble High Court and Hon'ble NGT, and the relevant Government Orders, the Jhansi Development Authority has failed to take concrete action and has directly or indirectly provided protection to the offenders.

26. That illegal constructions and tree felling have taken place in blatant violation of the documents, Master Plan, orders and environmental laws submitted by the Applicant, and the officers of the Jhansi Development Authority (Respondent No. 9), due to personal interest and corruption, have attempted to conceal the same.

27. That large-scale environmental degradation is being carried out on the hill/green area land reserved for the Sectoral Park in the Jhansi Master Plan, in connivance with the officers of the Jhansi Administration and the Jhansi Development Authority. Hundreds of trees and the natural hill are being cut, and unauthorized and illegal constructions in the form of nursing homes, pathology centers, medical stores, commercial establishments and residential buildings are being raised, thereby causing severe adverse impact on the environment, green balance and ecological system of the area.

Since the aforesaid land is clearly reserved as a Sectoral Park/Green Belt in the Jhansi Master Plan, any kind of commercial, institutional or residential construction thereon is not only contrary to the existing land use regulations, but also clearly indicative of direct violation of the provisions of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, the Parks Land Protection Act, 1975 and the Environment (Protection) Act, 1986.

28. That large-scale environmental degradation and illegal constructions are being carried out on the hill/green area land reserved for the Sectoral Park in the Jhansi Master Plan in connivance with the officers of the Jhansi Administration, Jhansi Municipal Corporation and Jhansi Development Authority (JDA). The officers of the respondent Municipal Corporation and Development Authority, with the intent to protect the said illegal constructions and to conceal the true facts, have deliberately submitted false, fabricated and misleading replies, thereby not only wasting the valuable time of the Hon'ble Tribunal but also making a clear attempt to mislead the judicial process.

The main points of the rejoinder dated 10.11.2025 (Document Nos. 458–488) submitted on behalf of the Applicant, Dr. Ajay Kumar.

1) प्रतिवादी संख्या 9, झांसी विकास प्राधिकरण का उत्तर पूर्णतः असत्य, भ्रामक एवं मनगढ़ंत है, जिसे माननीय न्यायाधिकरण को गुमराह करने एवं अवैध निर्माणों को संरक्षण देने के उद्देश्य से दाखिल किया गया है।
2) आवेदन में लगाए गए सभी आरोपों का सामान्य एवं निराधार खंडन किया गया है, जबकि मूल आवेदन के साथ प्रासंगिक अभिलेख, शासनादेश, मास्टर प्लान एवं फोटोग्राफ संलग्न हैं, जिनका प्रतिवादीगण द्वारा कोई तथ्यात्मक खंडन नहीं किया गया।
3) नोटिस जारी होने की तिथि के संबंध में प्रतिवादी संख्या 9 का कथन असत्य है। वास्तविकता यह है कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 30.07.2024 को नोटिस जारी किया गया था, जिसे आवेदक द्वारा 14.08.2024 को सभी प्रतिवादियों को प्रेषित किया गया।
4) क्षेत्र एवं खसरा/सर्वेक्षण संख्या न बताए जाने का आरोप झूठा है, क्योंकि प्रखण्डीय पार्क का स्पष्ट भौगोलिक विवरण (मेडिकल कॉलेज, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से लगी पहाड़ी भूमि) आवेदन में वर्णित है।
5) मौजा पिछोर की खसरा संख्या 1000M/1386 (9.5260 हेक्टेयर) सहित अन्य विवरण रिकॉर्ड पर उपलब्ध हैं और IA No. 560/2025 में अतिरिक्त खसरा संख्याओं एवं अवैध निर्माणों का भी खुलासा किया गया है।
6) प्रखण्डीय पार्क झांसी महायोजना 2001 एवं 2021 में विधिवत आरक्षित है, और इसे नई झांसी महायोजना 2031 में भी यथावत दर्शाया गया है, जिसे स्वयं प्रतिवादी संख्या 9 द्वारा संलग्न नक्शों से पुष्टि होती है।
7) अनधिकृत निर्माणों पर त्वरित कार्यवाही का दावा पूरी तरह झूठा है। वास्तविकता में सैकड़ों वृक्षों की कटान, पहाड़ी/ढलान का विनाश, नर्सिंग होम, पैथोलॉजी, मेडिकल स्टोर, व्यावसायिक एवं आवासीय अवैध निर्माण, झांसी प्रशासन एवं JDA अधिकारियों की मिलीभगत से किए जा रहे हैं। जिसे संलग्न फोटोग्राफ में स्पष्ट देखा जा सकता है।
8) महायोजना 2021 एवं 2031 के नक्शों में प्रखण्डीय पार्क की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्शित है, जिसे प्रतिवादी द्वारा भी स्वीकार किया गया है, फिर भी तथ्य छुपाए गए हैं।
9) झांसी विकास प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर लगभग एक वर्ष से अधिक समय तक कोई उत्तर दाखिल नहीं किया गया था, जिससे अवैध निर्माणों को संरक्षण मिला और विधिक जवाबदेही से बचने का प्रयास हुआ।
10) राज्य शासन के अनिवार्य शासनादेशों (16.01.2019 एवं 19.02.2020) का खुला उल्लंघन किया गया, जिनमें आरक्षित पार्क/ग्रीन बेल्ट की खसरा सूची वेबसाइट पर अपलोड करने, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग को विवरण उपलब्ध कराने, अवैध निर्माणों का तत्काल सर्वे कर कार्यवाही के स्पष्ट निर्देश थे।
11) OA No. 380/2018 एवं OA No. 114/2021 में माननीय NGT द्वारा पारित आदेशों का आज तक अनुपालन नहीं किया गया, जो गंभीर अवमानना एवं प्रशासनिक लापरवाही को दर्शाता है।
12) उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का जानबूझकर प्रयोग नहीं किया गया, जबकि अवैध निर्माण रोकने, हटाने एवं सील करने के स्पष्ट अधिकार उपलब्ध हैं।
13) अनधिकृत कालोनियों एवं अवैध निर्माणों के विरुद्ध FIR एवं कठोर कार्यवाही संबंधी शासनादेश (09.08.2018) का भी पालन नहीं किया गया।
14) झांसी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों की अवैध निर्माणों में सक्रिय संलिप्तता एवं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं, जिनमें रिश्वत लेकर पार्क/ग्रीन बेल्ट भूमि पर निर्माण कराने की शिकायतें शामिल हैं।
15) पार्क, हरित क्षेत्र एवं सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973, पार्क भूमि संरक्षण अधिनियम, 1975 तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है।
16) प्रखण्डीय पार्क हेतु आरक्षित पहाड़ी/हरित क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है, जिससे हरित संतुलन, पारिस्थितिकी तंत्र एवं जनस्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
17) प्रतिवादी अधिकारियों द्वारा झूठा एवं भ्रामक उत्तर प्रस्तुत कर न्यायिक प्रक्रिया को गुमराह किया गया है, जिससे माननीय न्यायाधिकरण का बहुमूल्य समय नष्ट हुआ।
18) न्यायहित एवं पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से स्वतंत्र जांच समिति/निरीक्षण दल का गठन अनिवार्य है, जो उपरोक्त प्रखण्डीय पार्क और पहाड़ के कुल रकबे, खसरा/गाटा संख्या, अवैध निर्माणों, दोषी निर्माणकर्ताओं,

उत्तरदायी अधिकारियों, पर्यावरणीय क्षरण एवं पुनर्स्थापनात्मक क्षतिपूर्ति का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

1) That the reply submitted by Respondent No. 9, Jhansi Development Authority, is wholly false, misleading and fabricated, and has been filed with the intent to mislead the Hon'ble Tribunal and to provide protection to illegal constructions.

2) That all the allegations raised in the Application have been denied in a general and baseless manner, whereas relevant records, Government Orders, Master Plans and photographs have been annexed with the Original Application, which have not been factually rebutted by the Respondents.

3) That the statement of Respondent No. 9 regarding the date of issuance of notice is false. In fact, the Hon'ble Tribunal issued notice on 30.07.2024, which was served upon all the Respondents by the Applicant on 14.08.2024.

4) That the allegation regarding non-disclosure of the area and Khasra/Survey numbers is false, as the Application clearly describes the geographical location of the Sectoral Park, namely the hill land adjoining the Medical College and Bundelkhand University.

5) That Khasra No. 1000M/1386 (area 9.5260 hectares) of Mouza Pichhor along with other details are available on record, and additional Khasra numbers and illegal constructions have also been disclosed in IA No. 560/2025.

6) That the Sectoral Park is duly reserved in the Jhansi Master Plan 2001 and 2021, and has also been shown as such in the new Jhansi Master Plan 2031, which stands confirmed from the maps annexed by Respondent No. 9 itself.

7) That the claim of taking prompt action against unauthorized constructions is completely false. In reality, large-scale felling of hundreds of trees, destruction of the hill/slope, and illegal constructions in the form of nursing homes, pathology centres, medical stores, commercial establishments and residential buildings are being carried out in connivance with the officers of the Jhansi Administration and JDA, which is clearly evident from the annexed photographs.

8) That the location of the Sectoral Park is clearly depicted in the maps of the Master Plan 2021 and 2031, which has also been admitted by the Respondent, yet the material facts have been concealed.

9) That the Jhansi Development Authority deliberately failed to file its reply for a period of more than about one year, thereby providing protection to illegal constructions and attempting to evade legal accountability.

10) That there has been an open violation of the mandatory Government Orders dated 16.01.2019 and 19.02.2020, which categorically directed uploading of Khasra lists of reserved parks/green belts on the website, providing details to the Stamp and

Registration Department, and conducting immediate surveys and taking action against illegal constructions.

11) That the orders passed by the Hon'ble NGT in OA No. 380/2018 and OA No. 114/2021 have not been complied with till date, which reflects serious contempt and administrative negligence.

12) That the powers conferred under the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973 have been deliberately not exercised, despite the availability of clear powers to stop, remove and seal illegal constructions.

13) That the Government Order dated 09.08.2018 relating to lodging of FIRs and taking stringent action against unauthorized colonies and illegal constructions has also not been complied with.

14) That there are serious allegations of active involvement and corruption on the part of the officers of the Jhansi Development Authority in illegal constructions, including complaints of taking bribes and facilitating constructions on park/green belt land.

15) That illegal constructions on parks, green areas and public land constitute a direct violation of the Uttar Pradesh Urban Planning and Development Act, 1973, the Parks Land Protection Act, 1975 and the Environment (Protection) Act, 1986.

16) That large-scale environmental degradation is taking place in the hill/green area reserved for the Sectoral Park, causing serious adverse impact on green balance, the ecological system and public health.

17) That by submitting false and misleading replies, the Respondent officers have misled the judicial process, resulting in wastage of the valuable time of the Hon'ble Tribunal.

18) That in the interest of justice and environmental protection, constitution of an independent inquiry committee/inspection team is imperative to conduct a scientific and objective assessment of the total area of the aforesaid Sectoral Park and hill, Khasra/Gata numbers, illegal constructions, guilty builders, responsible officers, environmental degradation and restorative compensation, and to submit its report accordingly.

13. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1, 3, 4, 8, 9 एवं 10 द्वारा प्रस्तुत उत्तर में किए गए कथन अपूर्ण, तथ्यहीन, असत्य, मनगढ़ंत एवं भ्रामक हैं, जिन्हें आवेदक पूर्णतः अस्वीकार करता है। उक्त कथन न तो अभिलेखीय साक्ष्यों से समर्थित हैं और न ही विधिक कसौटी पर खरे उतरते हैं, जो माननीय न्यायाधिकरण द्वारा भी अस्वीकार किए जाने योग्य हैं।

13. That the statements made in the reply submitted by Respondent Nos. 1, 3, 4, 8, 9 and 10 are incomplete, baseless, false, fabricated and misleading, which are wholly denied by the Applicant. The said statements are neither supported by documentary

evidence nor do they stand the test of law, and therefore are liable to be rejected by the Hon'ble Tribunal.

14. यह कि प्रतिवादी संख्या 7 तथा 10 की मौन स्वीकृति, सहभागिता और संरक्षण में भू-माफियाओं द्वारा उपरोक्त प्रखण्डीय पार्क एवं पहाड़ी भूमि पर वर्तमान में निरंतर पहाड़ी भूमि की कटान, वृक्षों के अवैध कटान कर अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। उक्त वास्तविक स्थिति को माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष समुचित रूप से प्रस्तुत करने हेतु यह अत्यंत आवश्यक एवं न्यायोचित है कि उपर्युक्त प्रखण्डीय पार्क एवं पहाड़ी भूमि पर विद्यमान अतिक्रमणों एवं अवैध निर्माणों की पहचान, सत्यापन एवं सम्यक सर्वेक्षण के लिए एक **स्वतंत्र संयुक्त समिति/विशेषज्ञ समिति** का गठन किया जाए।

14. That the acts of tacit approval, participation, and protection by Respondents No. 7 and 10 have facilitated the continued encroachment and illegal constructions on the above-mentioned Prakhandiya Park and hilly land by land mafias, including ongoing cutting of hilly land and illegal felling of trees. In order to present the actual situation accurately before this Hon'ble Tribunal, it is both necessary and just that an **independent Joint Committee/Expert Committee** be constituted for the identification, verification, and comprehensive survey of the encroachments and illegal constructions existing on the said Prakhandiya Park and hilly land.

15. यह समिति मूल आवेदन, प्रतिउत्तर, सबमिशन प्रार्थना पत्र और प्रतिवादियों के प्रत्युत्तर/हलफनामों का परिशीलन करते हुए, राजस्व अभिलेखों, खतौनी, झांसी महायोजना–2001, 2021 एवं 2031 के सजरा मानचित्र, गाटा संख्या तथा रकबा के अनुरूप स्थलीय निरीक्षण, सीमांकन एवं सर्वेक्षण कर वास्तविक स्थिति का निर्धारण करे। समिति अपनी कार्यवाही के आधार पर विस्तृत, तथ्यात्मक एवं दस्तावेज़-समर्थित अनुपालन रिपोर्ट माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करे।

15. That the said Committee shall, after examining the original application, replies, additional submissions, and the replies/affidavits of the Respondents, conduct on-site inspection, demarcation, and survey in accordance with the revenue records, khatauni, and the approved Zonal/Sajra Maps, Gata numbers, and area as per Jhansi Master Plans – 2001, 2021, and 2031, so as to ascertain the actual position on the ground. The Committee shall, based on its proceedings, submit a detailed, factual, and document-supported **compliance report** before this Hon'ble Tribunal.

(प्रार्थना)

अतः उपर्युक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं प्रस्तुत अभिलेखों के आलोक में, माननीय न्यायाधिकरण से सविनय प्रार्थना है किः-

क. आवेदक द्वारा प्रस्तुत इस *अतिरिक्त सबमिशन (Additional Submission)* तथा इसमें वर्णित तथ्यों एवं संलग्न समस्त अभिलेखों/दृश्य साक्ष्यों को माननीय न्यायाधिकरण के अभिलेख पर ग्रहण करने की कृपा करें।

ख. प्रतिवादियों द्वारा प्रेषित अपूर्ण, तथ्यहीन, असत्य, मनगढ़ंत एवं भ्रामक प्रत्युत्तर/हलफनामों को अवैध मानते हुए, पर्यावरण संरक्षण तथा विधि के प्रभावी अनुपालन के हित में उपर्युक्त पैरा 7 व 8 के उद्देश्य की पूर्ति हेतु उपरोक्त स्वतंत्र संयुक्त समिति/विशेषज्ञ समिति के गठन और संबंधित विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश पारित करने की कृपा करें।

ग. तथा न्यायहित, पर्यावरण संरक्षण एवं जल निकायों की रक्षा के उद्देश्य से माननीय न्यायाधिकरण जो अन्य आदेश/निर्देश उचित, न्यायसंगत एवं आवश्यक समझे, पारित करने की कृपा करें।

इसके लिए आवेदक सदैव आपका आभारी रहेगा।

(Prayer)

In view of the facts, circumstances, and the documents presented herein, the Applicant respectfully prays before this Hon'ble Tribunal as follows:

a. That this additional submission filed by the Applicant, along with all the facts stated herein and the annexed documents/visual evidence, may kindly be taken on record by this Hon'ble Tribunal.

b. That the incomplete, factually incorrect, false, fabricated, and misleading replies/affidavits submitted by the Respondents may be deemed illegal, and in the interest of environmental protection and effective enforcement of law, this Hon'ble Tribunal may be pleased to constitute the above-mentioned independent Joint Committee/Expert Committee for the purposes stated in paragraphs 7 and 8 above, and direct the submission of the detailed compliance report thereon.

c. That this Hon'ble Tribunal may be pleased to pass such other orders/directions as it may deem fit, just, and necessary in the interest of justice, environmental protection, and conservation of water bodies.

The Applicant shall, as always, remain ever grateful to this Hon'ble Tribunal.

दिनांक 17.01.2026

आवेदक

(भानू सहाय)
निवासी- 32, लक्षमनगंज, थाना कोतवाली,
जिला झांसी, उत्तर प्रदेश 284002
ई-मेल- bhanusahayjhs@gmail.com
मो. 9415588500

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 485/2024
(I.A. No. 560/2025)

Dr. Ajay Kumar & Ors. — Applicant(s)

Versus

Union of India & Ors. — Respondent(s)

I.A. No. 560/2025
(By Bhanu Sahay)

शपथ-पत्र

शपथकर्ता मिनजानिब - भानू सहाय पुत्र स्व. श्री वीरेन्द्र सहाय निवासी 32, लक्ष्मनगंज, थाना कोतवाली झांसी, उत्तर प्रदेश 284002

मैं शपथकर्ता उपरोक्त शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करता हूं:-

1. यह कि शपथकर्ता उपरोक्त प्रकरण में पक्षकार है एवं हालात प्रकरण से पूरी तरह से वाकिफ हैं। तथा अतिरिक्त सबमिशन देने में सक्षम है।
2. यह कि शपथकर्ता द्वारा उपरोक्त प्रकरण में अतिरिक्त सबमिशन प्रस्तुत किया जा रहा है।
3. यह कि शपथकर्ता द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त सबमिशन में सही-सही तथ्यों में तहरीर किया गया है। जिन्हें पुनः संक्षिप्त के कारण शपथपत्र में दोहराया नहीं जा रहा है इसलिए उन्हें इस शपथपत्र में अडॉप्ट किया जा रहा है जो इस शपथपत्र का भाग माना जावें।

मैं शपथकर्ता तस्दीक करता हूं कि वर्तमान शपथ पत्र की विषय-वस्तु मेरे निजी ज्ञान और जानकारी अनुसार सब सत्य और सही है तथा इसमें कोई भी महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह तस्दीक आज दिनांक 17.01.2026 को वमुकाम अहाता कचहरी झांसी में की गयी।

शपथकर्ता

Bhanu Sahai

GPS Map Camera
Jhansi, Uttar Pradesh, India
Gate No. 3, Ke Aage, Medical College, Arogya
Bharti Campus, Bundelkhand University, Jhansi,
Uttar Pradesh 284128, India
Lat 25.461317° Long 78.619203°
14/01/2026 02:21 PM GMT +05:30
Check In
Google

GPS Map Camera
Jhansi, Uttar Pradesh, India
Gate 3, Basic Building, Bundelkhand University Rd, Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh 284001, India
Lat 25.454325° Long 78.612828°
14/01/2026 02:01 PM GMT +05:30
Check In
Google

GPS Map Camera
Jhansi, Uttar Pradesh, India
Fj37+85c, Karguan Gaon, Jhansi, Uttar Pradesh
284128, India
Lat 25.453715° Long 78.612539°
14/01/2026 02:00 PM GMT +05:30
Check In
Google

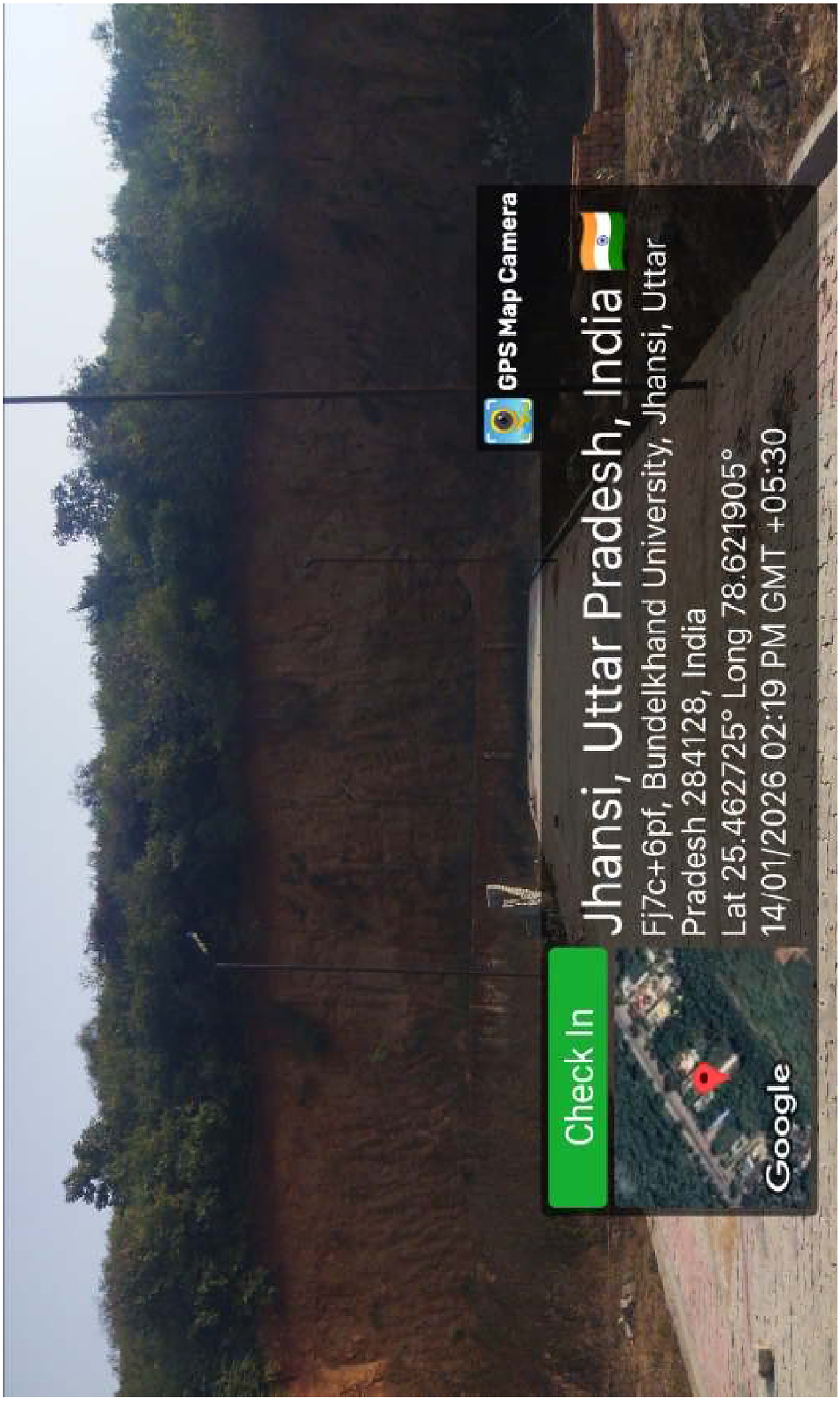
GPS Map Camera
Jhansi, Uttar Pradesh, India
Fj7c+6pf, Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh 284128, India
Lat 25.462725° Long 78.621905°
14/01/2026 02:19 PM GMT +05:30
Check In
Google

525

GPS Map Camera
Jhansi, Uttar Pradesh, India
Gate No. 3, Ke Aage, Medical College, Arogya Bharti Campus, Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh 284128, India
Lat 25.461315° Long 78.61922°
14/01/2026 02:21 PM GMT +05:30
Check In
Google

GPS Map Camera
Check In
Jhansi, Uttar Pradesh, India
2nd Floor, Hi-tech Hospital, Opp. Medical College Gate No. 4 Near Parag Milk Dairy, Kanpur, Road, Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh 284128, India
Lat 25.463958° Long 78.624211°
14/01/2026 02:16 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Check In
Jhansi, Uttar Pradesh, India
Gate No. 3, Ke Aage, Medical College, Arogya Bharti Campus, Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh 284128, India
Lat 25.461294° Long 78.619225°
14/01/2026 02:21 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Check In
Jhansi, Uttar Pradesh, India
Fj7c+6pf, Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh 284128, India
Lat 25.462726° Long 78.62192°
14/01/2026 02:19 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Check In
Jhansi, Uttar Pradesh, India
Fj47+frr, Dandiyapura, Bundelkhand University,
Jhansi, Uttar Pradesh 284128, India
Lat 25.456402° Long 78.614636°
14/01/2026 02:04 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Check In
Jhansi, Uttar Pradesh, India
Infront Of Medical College Gate No. 1, Amyur Vihar Colony, Adj. Yadav Medical Wali Gali, Bundelkhand University, Jhansi, Uttar Pradesh 284128, India
Lat 25.455976° Long 78.614181°
14/01/2026 02:03 PM GMT +05:30
Google

GPS Map Camera
Check In
Jhansi, Uttar Pradesh, India
Fj47+787, Nh 25, Bundelkhand University, Jhansi,
Uttar Pradesh 284128, India
Lat 25.45575° Long 78.613751°
14/01/2026 02:02 PM GMT +05:30
Google